

प्रेषक,

केशव देसिराजु  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग- 5

देहरादून: दिनांक: 24 मई, 2009

विषय: उत्तराखण्ड के नव सृजित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रबन्धन हेतु सम्बंधित जनपदों में सी0डी0ओ0 की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबन्धन समितियों के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-84/एन0पी0/आर0के0एस0/सी0एच0सी0 पी0एच0सी0/08-09 दिनांक 14.11.08 तथा उत्तराखण्ड राज्य में पूर्व स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रबन्धन हेतु चिकित्सा प्रबन्धन समिति गठित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 840/XXVIII-05-2006-42/2003 दिनांक 29.09.2006 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के नव सृजित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रबन्धन में लोच एवं गतिशीलता तथा चिकित्सीय सेवा की गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के सन्दर्भगत चिकित्सा संस्थानों के प्रबन्धन हेतु संलग्न सूची के अनुसार सम्बंधित जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबन्धन समिति का गठन किया जाए। अतः इस हेतु यथोत्लिखित शासनादेश द्वारा प्रेषित, अनुमोदित संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद के अनुसार चिकित्सा प्रबन्धन समितियों का गठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत शीघ्रातिशीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित कर शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

2- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के यूजर चार्ज के रूप में मिलने वाली समस्त धनराशि चिकित्सा प्रबन्धन समिति को दी जायेगी। आप अवगत है कि वर्तमान में यूजर चार्ज के रूप में मिलने वाली धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि राजकोष में जमा की जाती है। अतः यूजर चार्ज के रूप में अतिरिक्त 50 प्रतिशत दी जाने वाली धनराशि को शासन से चिकित्सालय को मिलने वाले अनुदान में से उसी अनुपात में घटा दी जायेगी तथा समिति को चिकित्सालय के संचालनार्थ विभिन्न मानक मदों के स्थान पर एक मुश्त बजट अनुदान के रूप में 50 प्रतिशत अतिरिक्त यूजर चार्ज घटा कर दिया जायेगा। चिकित्सालयों में सृजित पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्त पूर्ववत् रहेंगी तथा उन्हें जो वेतन व परिलब्धियाँ आदि राज्य बजट से दी जा रही हैं, भविष्य में भी इसी प्रकार दी जाती रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के असा० सं०-896(1) (P)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/2008 दिनांक: 17.3.09 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(केशव देसिराजु)  
प्रमुख सचिव

संख्या 457 (1)/XXVIII-S-2009-60/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, भाजरा देहरादून।
- 2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड।
- 3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 8- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10- समस्त अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उत्तराखण्ड।
- 11- वित्त अनुभाग-3/एन०आई०सी०
- 12- गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)  
उप सचिव

शासनादेश संख्या 657 XXVIII-S-2009-42/2003 दिनांक 29 मई 2009 का संलग्नक

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची

क्र.स.	जनपद	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम
1.	उत्तरकाशी	1. चिन्यालीसोड
2.	हरिद्वार	2. खानपुर 3. बहादुराबाद 4. मंगलौर
3.	देहरादून	5. रायपुर 6. सहसपुर